VOL- XI | ISSUE- VII | JULY | 2024 | PEER REVIEW e-JOURNAL | IMPACT FACTOR 8.02 | ISSN 2349-638x

भारतिय राजनीति में जाति की भूमिका

सहायक आचार्य बनवारीलाल
M.A Political Science, RSLET
Ex. – Ch. K.R. Girls College New Gharsana
(Sri Ganganagar)

शोध आलेख सार-

भारतीय समाज ही नहीं बल्कि राजनीति में जाति की विशिष्ट भूमिका है। भारतीय राजनीति का विश्लेषण जातियों के वि 'श्लेषण के बगैर अपूर्ण है। सुरेन्द्र एस. जोधका के अनुसार जाति एक 'संस्था भी है और एक 'विचारधारा' भी। संस्थागत रूप में जाति सामाजिक समूहों को उनकी प्रस्थिति तथा सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में उनकी स्थिति का निर्धारण करती है। एक विचारधारा के रूप में जाति उन मूल्यों व विचारों की एक व्यवस्था है जो सामाजिक असमानता की मो मौजुदा सरंचनाओं को बैदता प्रदान करती है ।

1. भारत में जाति ऐसे समुदाय है जिसका अपना विकसित जीवन है और जातियों के पद सोपान से निश्चित होती है।

2. जातियों के आधार पर खान- पान और सामाजिक आदान-प्रदान के प्रतिवन्ध लगे रहते है।

3. जातियों की परिधि में ही वैवाहिक आदान प्रदान होता है।

शोध प्रविधि-

सामाजिक परिवर्तन समाज की एक अनवरत् प्रक्रिया है जो समाज में निरंतर रूप से चलती है और चलनी चाहिए क्योंकि इसी के कारण कोई समाज या सभ्यता अपना विकास करते है । इस सामाजिक परिवर्तन को गतिशील करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन ज्ञान का विकास है। ज्ञान का विकास सतत् शोध के अभाव में अधूरा है। अत: शोध ज्ञान के अभाव में अधूरा है। अतः शोध ज्ञान के विकास की पूर्वशर्त है। 'शोध' शब्द का प्रयोग एक प्रकार से शुद्धि, संस्कार या संशोधन के अर्थ के रूप में किया जाता है।

जाति–राजनीतिक व्यवहार मे

जातिय – राजनीतिक प्रतिव्दन्व्दता-

- राजस्थान - राजपूत व जाट
- आन्ध्रा - कामा व रेड्डी
- केरला - इजवाह v/s ब्राह्मण
- कर्नाटक - लिंगायत v/s वेककालिंगा
- **अजगर** – अहीर+ जाट + गुर्जर + राजपूत= यू.पी.मे। चौधरी चरण सिंह छोटू राम द्वारा हरित क्रांति के बाद कांग्रेस के एका अधिकार को तोड़ने के लिए ।
- **मजगर** - अजगर + मुस्लिम = यू.पी.में
- **खान (गुजरात)** - क्षत्रिय (कोली, ठाकुर) + हरिजन + आदिवासी + मुस्लिम
- **खाम्प** - (खाम) + पटेल

गुजरात के 2017 के विधान सभा चुनाव ने भरत सिंह सोलंकी द्वारा पाटीदारों (पटेलों) को खाम में शामिल किया ।

राजनीति पर जाति का सकारात्मक प्रभाव –

- **जातिगत एकजुटता** : पिछले सौ सालों में जातिगत एकजुटता की भावना में वृद्धि हुई है। शिक्षित नेताओं ने जाति के गरीब सदस्यों की मदद के लिए धन इकट्ठा किया है, जाति सम्मेलन आयोजित किए हैं, जाति छात्रावास, अस्पताल, सहकारी समितियाँ बनवाई हैं। जीएस घुर्ये ने 1932 में ही तर्क दिया था कि जाति पदानुक्रम पर हमला भारत में जाति का अंत नहीं है, बल्कि इसने ' जातिगत एकजुटता ' की

एक नई भावना को जन्म दिया है जिसे जातिगत देशभक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

- **जाति समूह और गठबंधन** : ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन में पिछड़े वर्ग के लोगों को काफी रियायतें दीं। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए, पारंपरिक जाति समूहों ने एक-दूसरे के साथ गठबंधन किया और इस प्रकार बड़ी इकाइयाँ बनाईं। इसने जाति समूहों और गठबंधनों की नींव रखी जो आज भी एक ही जाति के लोगों को संगठित और संगठित करते हैं
- **जाति और वंचितों का सशक्तिकरण** : इसने वंचित समुदाय के लोगों को सत्ता में अपना उचित हिस्सा मांगने का मौका दिया है। जाति की राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों को निर्णय लेने में बेहतर पहुंच प्रदान की है। जातिगत एकजुटता उनके लिए सुरक्षा जाल बन गई है, जिससे उन्हें बेहतर प्रतिनिधित्व की गारंटी मिलती है।
- **भारतीय राजनीति में जाति एक संयोजक शक्ति के रूप में** : यह समूह के सदस्यों के बीच एकता का स्रोत है और एक संयोजक शक्ति के रूप में कार्य करती है।

भारत में जातिगत राजनीति के प्रचलन के कारण वंचितों और हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए: नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976

जाति -**आधारित राजनीतिक दल** भी **निचली जातियों के लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं** , उन्हें संगठित कर रहे हैं और राजनीतिक रूप से जागरूक बना रहे हैं।

- **जाति संघों ने उन क्षेत्रों में भी लोकतांत्रिक राजनीति की संस्कृति को फैलाने** में भूमिका निभाई है, जो पहले परंपरा से शासित थे।
- जाति संघ **दबाव समूहों** के रूप में भी कार्य करते हैं जो निम्न जाति के लोगों के विचारों को सुदृढ़ करते हैं, जिससे उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व मिलता है।

राजनीति पर जाति का नकारात्मक प्रभाव-

भारतीय राजनीति में जाति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय राजनीति में जाति से जुड़े कुछ नकारात्मक पहलू नीचे दिए गए हैं :

राजनीतिक और सामाजिक तनाव में वृद्धि

- जाति आधारित राजनीति अक्सर राजनीतिक और सामाजिक तनाव को बढ़ाती है। प्रतिस्पर्धी जाति समूह सत्ता, संसाधनों और प्रतिनिधित्व के लिए लड़ते हैं।
- जाति-आधारित लामबंदी विभाजन पैदा कर सकती है। यह समुदायों के बीच संघर्ष पैदा कर सकती है। यह अंतर-जातीय प्रतिद्वंद्विता और सामाजिक विखंडन को भी जन्म देती है।

सरकार की नीतियां और निर्णय

- इसका नतीजा ऐसी नीतियों और निर्णयों में हो सकता है जो विशिष्ट जाति हितों को प्राथमिकता देते हैं। कभी-कभी ये नीतियां समाज के कल्याण में नहीं होती हैं।
- सरकारी संसाधन और विकास पहलों का आवंटन जातिगत आधार पर किया जा सकता है। इससे असमानताओं और हाशिए पर पड़े समूहों की ज़रूरतों की अनदेखी होती है।

लोकतांत्रिक आदर्श

जाति आधारित राजनीति लोकतंत्र के आदर्शों को कमजोर कर सकती है। लोकतंत्र समान प्रतिनिधित्व, निष्पक्षता और समावेशिता पर जोर देता है।

जाति आधारित मतदान पैटर्न में जाति पहचान को प्राथमिकता दी जा सकती है। इससे अन्य कारकों की अनदेखी होती है जैसे कि क्षमता, सत्यनिष्ठा और नीतिगत स्थिति तथा सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता होता है।

भारतीय राजनीति में जाति विभाजनकारी है या एकजुटता का कारक?

जाति-आधारित विभाजन अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर हावी हो सकता है जैसे:

- विकास
- सुशासन
- सामाजिक न्याय

जाति-आधारित गठबंधन और लामबंदी अक्सर विशिष्ट जातियों के हितों को प्राथमिकता देते हैं। इससे बहिष्कार की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। यह हाशिए पर पड़े समुदायों की चिंताओं की भी उपेक्षा करता है।

भारतीय राजनीति में जाति की नकारात्मक भूमिका को स्वीकार करते हुए, इन चुनौतियों को कम करने की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में अधिक समावेशी और योग्यता आधारित राजनीतिक व्यवस्था को शामिल करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए :

- सामाजिक एकता को बढ़ावा देना
- जाति आधारित भेदभाव को कम करना
- नीतियों को प्राथमिकता देना

समाज के सभी वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। यह अधिक न्यायसंगत और प्रगतिशील राजनीतिक माहौल में योगदान दे सकता है। राजनीतिक विमर्श और व्यवहार में समानता , न्याय और समावेशिता के सिद्धांतों पर ज़ोर देना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे भारतीय राजनीति में जाति के नकारात्मक प्रभावों को दूर किया जा सकता है और एक मज़बूत लोकतंत्र का निर्माण किया जा सकता है।

जातियों का राजनीतिकरण-

- कोठारी का दावा है कि भारतीय जाति प्रथा आधुनिक संसदीय राजनीति में भागीदारी करके समाज परिवर्तन की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है। जाति और राजनीति के मेल के कारण बिना किसी भारी उथल-पुथल के समाज का सेकुलरीकरण जारी है। इसी वजह से लोकतंत्र में आम जनता सक्रिय हुई है और इस राज्य व्यवस्था को उसकी विशिष्ट शक्ल मिल सकी है।
- दरअसल, राजनीति एक ऐसी स्पर्धात्मक कार्यवाही है जो पहले से मौजूद और नयी उभरती हुई निष्ठाओं की शिनाख्त करके उनका अपने हक में इस्तेमाल करती है। जाति और राजनीति को नज़दीक लाते हुए इस प्रक्रिया ने दोनों के रूपों को बदला है। संगठन के दायरे में जाति को लाते हुए राजनीति ने उससे अपनी अभिव्यक्ति की सामग्री प्राप्त की है और उसे अपनी योजना के मुताविक ढाला है। जबकि जाति समूहों ने राजनीति को अपनी गतिविधियों का केंद्र बना कर अस्मिता का दावा पेश करने और राज्य तंत्र में अपनी स्थिति सुधारने का मौका हासिल किया है।
- कोठारी यह भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि भारतीय राजनीति में भागीदारी करके जाति का लोकतांत्रिक पुनर्जन्म हो गया है। ये कहते हैं कि सोचने के ये सभी तरीके जाति और राजनीति के प्रचलित 'अंतर्विरोध' से निकलने वाले द्विभाजन के शिकार हैं

अन्य महत्त्वपूर्ण कथन —

- **जय प्रकाश नारायण-** "भारत में जाति सबसे बड़ा राजनीतिक दल है।"
- **टिंकर** — "राज्यों की राजनीति मूलतः जातियों की राजनीति है।"
- **क्रिस्टोफर जेफटलॉ- मौन क्रांति** (Silent Revolution)
- **जी.एस. घुर्ये / घुरिये** — जाति-भक्ति (Cast-Patriotism)
- **जी एस. घुरिये** - "जाति की एकजुटता जाति-भक्ति के रूप में "
- **आन्द्रे बैते-** "आरक्षण से पिछड़ेपन की दौड़ शुरू हुई है।"
- **बैलगाड़ी पूँजीवाद** — रूडोल्फ व रूडोल्फ
- **माइकल ब्रेचर** — "अखिल भारतीय राजनीति की बजाए राज्य स्तरीय राजनीति में जाति का ज्यादा प्रभाव है।"
- **इंदिरा साहनी वाद** (1993) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जाति व वर्ग एक दूसरे के पूरक है।

सारांश-

जाति, भारतीय राजनीति में जोड़ने वाली एवं बाँटने वाले दोनों कारकों की तरह कार्य करती है। यह विभिन्न हित समूहों के उदय का कारण बन गयी है जो सत्ता एवं पहचान के लिए संघर्ष करते हैं। इस जाति चेतना ने भारतीय राजनीति में नयी प्रवृत्ति को जन्म दिया है जिसमें पुराने जाति गठबंधन टूट रहे हैं एवं नये गठबंधन बनकर उभर रहे हैं। आधुनिक राजनीति के प्रभाव के अंतर्गत जातिवादी संगठन राजनीतिक लामबंदी का मुख्य आधार बन चुके हैं। ये राजनीतिक सत्ता

हासिल करने, सामाजिक हैसियत, एवं आर्थिक स्थिति मजबूत करने के इरादे से उभर कर सामने आये हैं। जो जाति समूह, जिन्हें निम्न समझा जाता था, अब वे संगठित होकर अपनी माँगों के लिये दबाव बना रहे है। अपने आत्म विश्वास तथा स्तर में वृद्धि एवं साख में वृद्धि के कारण, ये राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं एवं अपनी स्थिति या पहचान मजबूत कर रहे हैं। इस प्रकार राजनीति जाति के लिये एवं जाति राजनीति के लिए महत्वपूर्ण बन गयी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सुची -

1. भारतीय राजनीति व्यवस्था - बी.एल. फड़िया एवम पुखराज जैन
2. समाचार पत्रों का संग्रह – राजस्थान पत्रिका
3. राज व्यवस्था – एनसीईआरटी पुस्तक

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com